ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS THEREON

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-*106
ANSWERED ON- 16/12/2022

INCLUSION OF COTTON IN ESSENTIAL COMMODITIES ACT

*106. SHRI ABIR RANJAN BISWAS:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the yearly increase in the export of cotton yarn/fabric since 2019, year-wise details thereof;

(b) the price of a kilogram of raw cotton compared to the price of a kilogram of garment exported with value addition fetched in the international market, the details thereof;

(c) whether Government is considering including cotton in the Essential Commodities Act, considering the dominant position of cotton and the shortage of raw cotton in textile industry, if so, the details thereof; and

(d) whether Government is considering to remove basic Custom Duty and Agriculture Infrastructure Development Cess levied on the import of cotton?

ANSWER

THE MINISTER OF TEXTILES
(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to the Rajya Sabha Starrerd Question no. *106 to be answered on 16.12.2022 by SHRI ABIR RANJAN BISWAS regarding "Inclusion of cotton in Essential Commodities Act"

(a): The detail of yearly percentage increase in the export of cotton yarn/fabric is annexed.

(b): There is no such information available with the Ministry.

(c): There is no such proposal at present. There is adequate availability of cotton in the country as the estimated cotton production is 341.91 lakh bales and consumption is 311 lakh bales.

(d): As of now there is no such proposal.

Annexure

EXPORT OF COTTON YARN
(Including Sewing Thread)

YEAR	Qty (Mn tonne)
2018-2019	1.26
2019-2020	0.96
2020-2021	1.011
2021-2022	1.39

Export of Cotton Fabrics

YEAR	Qty (Mn Sqm.)
2018-2019	1739.61
2019-2020	1877.04
2020-2021	1770.37
2021-2022	2374.48

***

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *106
16 दिसंबर, 2022 को जवाब दिया

कपास को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करना

***106. श्री अबीर रंजन बिस्वास:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से सूती धागे/कपड़े के निर्यात में हुई वृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) निर्यातित परिधानों की प्रति किलोग्राम कीमत की तुलना में प्रति किलोग्राम कच्चे कपास की कीमत कितनी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने पर इसका कितना वर्धित मूल्य मिलता है;
(ग) क्या सरकार कपड़ा उद्योग में कपास की बहुलता और कच्चे कपास की कमी को ध्यान में रखते हुए इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करने पर विचार कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार कपास के आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर को समाप्त करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘कपास को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल करना’ के संबंध में दिनांक 16.12.2022 को श्री अबीर रंजन बिस्वास द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *106 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कपास यार्न/फैब्रिक के निर्यात में वार्षिक प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा संलग्न है।

(ख): मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। देश में कपास की पर्याप्त उपलब्धता है क्योंकि अनुमानित कपास उत्पादन 341.91 लाख गांठ और खपत 311 लाख गांठ है।

(घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

<u>अनुबंध</u>

कॉटन यार्न का निर्यात
(सिलाई के धागे सहित)

वर्ष	मात्रा (मिलि. टन)
2018-2019	1.26
2019-2020	0.96
2020-2021	1.011
2021-2022	1.39

कॉटन फैब्रिक का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मिलि. वर्गमीटर)
2018-2019	1739.61
2019-2020	1877.04
2020-2021	1770.37
2021-2022	2374.48

*****

श्री अनिल बलूनी : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो निर्यात में वृद्धि हुई है, वह सरकार के प्रयासों से हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मल्लिकार्जुन खरगे : सर, आप इतने इम्पॉर्टेंट इश्यू पर चर्चा की अनुमति दें ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय मेम्बर्स, हाउस के जो रूल्स हैं, उन रूल्स के अनुसार जो रोज़ का लिस्टेड बिज़नेस होता है, हाउस उसके अनुसार चलता है, यदि आप उसमें बदलाव चाहते हैं, तो आप उसके लिए नोटिस दीजिए, वह प्रॉपरली चेयरमैन साहब से स्वीकृत होगा। आप अपने आपसे चाहते हैं कि जो मैं कहूं, उस पर तुरंत बहस हो जाए, तो आप ऐसा नियम बनाइये। जो निर्धारित नियम हैं, सदन उन्हीं के अनुसार चलेगा।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि कपास के उत्पादन के कारण एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा है? मैं बताना चाहती हूं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्रीज़ आदि इन सभी को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है। खासकर पिछले दिनों कॉटन की क्वालिटी अच्छी हो जाए, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, आधुनिक उपकरणों के साथ उसकी गुणवत्ता के मूल्यांकन के साथ हमने उसका प्रोडक्शन बढ़ाया है, जिससे कि अच्छा रॉ-मैटिरियल मिलने से रेडिमेड गारमेंट्स और जो अन्य कॉटन आधारित चीजें बनती हैं, उनको बढ़ावा मिले।

श्री प्रेम चंद गुप्ता : उपसभापति महोदय, सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं, यदि हम उन्हें देखते हैं तो कॉटन यार्न और कॉटन फैब्रिक्स का जो एक्सपोर्ट हुआ है, उसमें कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, क्वांटिटीवाइज़, 2021-22 में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से सारी दुनिया में कॉटन फैब्रिक्स और कॉटन गारमेंट्स के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम इसमें बहुत पीछे हैं। आज के दिन जो हमारा कॉटन गारमेंट्स और फैब्रिक्स के एक्सपोर्ट का पूरा बिज़नेस है, यह बंगलादेश की तरफ जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में आप कोई ऐसा स्टेप उठा रही हैं कि हमारा जो बिज़नेस उधर जा रहा है, उसे हम वापस लायें और इसको आगे बढ़ायें।

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : महोदय, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तीन-चार सेक्टर्स के ऊपर टिकी हुई है। हमारा देश कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ा हुआ था और जिस तरह से कॉटन का प्रोडक्शन होता था, पूरी दुनिया मैन-मेड फाइबर को यूज़ करती है। इसके लिए हमारा वहां 25 परसेंट स्टेक ही था और हम जो कॉटन और इसके द्वारा निर्मित चीजों का प्रोडक्शन करते थे, उनका यूज़ इंडिया में ही होता था। परंतु जिस तरह से आपने कॉटन रेडिमेड गारमेंट्स के बारे में बताया, तो एक

स्कीम के माध्यम से फैब्रिक्स,मैन-मेड फाइबर और टेक्निकल टैक्सटाइल्स - इन तीनों कम्पोनेंट्स पर हम एक पीएलआई स्कीम लाये, जिसके कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया और यहां 47 कंपनियों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसके कारण आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए उस प्रोडक्शन में हमने बढ़ोतरी की है।

वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : महोदय, श्री प्रेम चंद जी की बात में बहुत तर्क है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कहूं। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, यह बात सच है कि गत कुछ वर्षों में बंगलादेश और वियतनाम - इन दोनों देशों ने कॉटन टेक्सटाइल और कॉटन गारमेंट्स के क्षेत्र में काफी बढ़त की है, लेकिन इसकी गहराई में जाना आवश्यक है। बंगलादेश अभी भी (एल.डी.सी.) लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है और 2026 तक वह एल.डी.सी. रहेगा, जिसके कारण उसको पूरी दुनिया के बाजारों में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। सिमिलरली वियतनाम के द्वारा यूरोपियन यूनियन, जो सबसे बड़ी मार्केट है, उनके साथ एफटीए करने से उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलता है। साधारणतः हमारे गारमेंट्स के ऊपर यूरोप में 9, 10 और 12 परसेंट ड्यूटी लगती है, जिसके कारण बंगलादेश और वियतनाम को लाभ हुआ और हम उसका लाभ ले नहीं पाये, क्योंकि 2013 में जो एफटीए की चर्चा यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही थी और अलग-अलग देशों के साथ बातचीत हो रही थी, उसको अबॉर्ट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो गत वर्षों में भारत का वर्चस्व बनाया है, पूरे विश्व में आज भारत एक ताकत के रूप में जो उभर रहा है, उसके कारण आज पुनः पूरे विश्व में सबकी इच्छा है कि भारत के साथ वे अपने ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स बढ़ाएँ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करें। आपके माध्यम से मुझे आप सबको सूचित करते हुए बड़ी खुशी होती है कि एक ही वर्ष में दो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ। यू.ए.ई. के साथ पहली मई से, the FTA has entered into force. साइन तो पहले ही हो गया था, but it has entered into force in a record time. ऑस्ट्रेलिया के साथ, 29 दिसम्बर से, the FTA will enter into force. इसके अलावा 6 के 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन से एफटीए की बात चल रही है, कनाडा से एफटीए की बात चल रही है, यू.के. से एफटीए की बात चल रही है। यह दिखाता है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और उसको दिख रहा है कि भारत आगे चल कर एक विश्वसनीय पार्टनर, ट्रस्टेड पार्टनर होगा। इसी की वजह से हमारे कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय, दोनों ने मिल कर एक टेक्सटाइल एडवाइज़री ग्रुप में फ्रॉम फार्म टू फॉरेन - जो माननीय प्रधान मंत्री जी कई बार फाइव-एफ्स कहते हैं - फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। ये जो फाइव-एफ्स हैं, इनकी पूरी वेल्यू चेन को एक साथ जोड़ा गया है। कृषि मंत्रालय भी हमारी बहुत मदद कर रहा है कि कॉटन की जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, उसको कैसे भारत में बढ़ाया जाए।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, कृपया ब्रीफली बोलिए।

श्री पीयूष गोयल : मैं इसमें थोड़ी लास्ट जानकारी दे देता हूँ। कल ही, वाराणसी में जो 'काशी तमिल संगमम्' हो रहा है, जिसमें तमिलनाडु और काशी का जुड़ाव और 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसके तहत देश भर के कॉटन टेक्सटाइल के लोग फ्रॉम फार्मर्स टू एक्सपोर्टर्स, सब इकट्ठे हुए थे, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और सबने संतुष्टि व्यक्त की है कि जिस प्रकार से तेज गति से कॉटन पर काम चल रहा है, आगे का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। माननीय श्री रविचंद्र वद्दीराजू।

श्री रविचंद्र वद्दीराजू : सर, हमारे तेलंगाना में हमारे केसीआर जी के नेतृत्व में, इस देश में जो कहीं भी इम्प्लिमेंट नहीं है, फार्मर्स और वीवर्स को सपोर्ट करते हुए राइथु बंधु स्कीम में 10,000 रुपये देने और 24 X 7 बिजली और पानी देने के कारण बहुत सारी क्रॉप्स आ गयी हैं, पैडी और कॉटन भी आयी हैं।

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री रविचंद्र वद्दीराजू : सर, यह क्वेश्चन ही है, आंसर नहीं है। मैं क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ। कॉटन का प्राइस बढ़ाने के लिए, 6,080 से लेकर 12,000 एमएसपी करने के लिए - हमारे यहाँ वीवर्स कम्युनिटी में लाखों लोग हैं, टेक्सटाइल के लिए 5 परसेंट जीएसटी है।

श्री उपसभापति : आप प्लीज़ सवाल पूछिए।

श्री रविचंद्र वद्दीराजू : सर, उसको हटाने के लिए लाखों पोस्टकाड्र्स दिये गये हैं। इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जीएसटी खत्म करने के लिए लिखा गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप सवाल पूछिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री रविचंद्र वद्दीराजू : सर, उसको हटाने के लिए और एमएसपी बढ़ाने के लिए ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप अपना सवाल पूछिए।...(**व्यवधान**)...

श्री रविचंद्र वद्दीराजू : सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : सर, जीएसटी के लिए जो भी बात होती है, वह फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा किसानों की आय दोगुना करने के लिए जो बोला है, तो कॉटन का सबसे ज्यादा पैसा, एमएसपी से ज्यादा पैसा इस समय मिला है।